

**THE PARLIAMENTARY DEBATES**  
**OFFICIAL REPORT**  
**IN THE HUNDRED AND SIXTY-SIXTH SESSION OF**  
**THE RAJYA SABHA**

*Commencing on the 22nd February, 1993/3rd Phalgma, 1914 (Saka)*

**RAJYA SABHA**

*Monday, the 22nd February, 1993/3rd Phalguna, 1914 (Saka)*

The House met at fifty one minutes past twelve of the clock.

Mr. Chairman in the Chair.  
*National Anthem*

(The National Anthem was played.)

**PRESIDENTS ADDRESS LAID ON  
THE TABLE**

SECRETARY-GENERAL : Sir—  
I beg to lay on the Table a copy (in Hindi and English), of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 22nd February, 1993. [Placed in Library see No LT.....93]

*[Text of the Address delivered by the President (Dr. Shanker Dayal Sharma) in Hindi]*

**माननीय सदस्यगण,**

संसद के इस अधिवेशन में, मैं आपका स्वागत करता हूँ।

हमारे सामने आज सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोगों के मन में उस विश्वास और साम्प्रदायिक सौहार्द को फिर से स्थापित करना है, जिसे पिछले वर्ष 6 दिसम्बर और उसके तत्काल बाद घटी दुखद

घटनाओं के कारण गहरा धक्का लगा है। धर्मनिरपेक्षता और विधि की सर्वोच्च सत्ता जैसी आधारभूत बातों को भी अब खतरा पैदा हो गया है। राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, प्रभावशाली नेताओं और अन्य प्रभावी लोगों को इस बढ़ते हुए साम्प्रदायिक कुप्रचार को रोकने के लिए मिलकर विरोध करना चाहिए, ताकि हम राष्ट्र निर्माण के कार्य में लग सकें और अपने आधारभूत मूल्यों को अधुण बनाए रख सकें। हमें साम्प्रदायिक सद्भाव की भावना को, जो कि सदैव ही हमारे समाज की विशेषता रही है, और अधिक मजबूत करना होगा।

राम जन्म भूमि—दाबरी मस्जिद विवाद के मुख्य मुद्दे को संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को भेजा जा चुका है। सरकार ने भी परिसर की लगभग 68 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और सरकार अब राम मंदिर तथा मस्जिद के निर्माण कार्य का संचालन करने के लिए दो पृथक न्यास गठित करने संबंधी कार्रवाई कर रही है। सरकार इस बात का भरसक प्रयास करेगी कि निर्माण कार्य दोनों संबंधित समुदायों की सलाह और सहयोग से और दोनों समुदायों के प्रमुख तथा जिम्मेदार नेताओं की सक्रिय भागीदारी से पूरा किया जाए। सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभी वर्गों के लोगों का समर्पण चाहती है और उनके सहयोग की अपेक्षा रखती है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को प्रशिक्षण और हथियार देने तथा संभारतंत्र का समर्थन देने में सीमापार के बलों की भूमिका में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। अत्यधिक कठिन स्थितियों में कार्य करने की मजबूरी के बावजूद हमारे सुरक्षा बल इस चुनौती का मुकाबला करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। राज्य में आतंकवादियों के कायरतापूर्ण कार्यों, बार-बार बंद का आह्वान किये जाने और आर्थिक तथा वाणिज्यिक क्रियाकलापों में रुकावट पैदा किये जाने आदि के कारण जम्मू और कश्मीर की जनता को जिस प्रकार की कठिनाई और तंगी का सामना करना पड़ रहा है, सरकार उसके प्रति पूरी तरह से सचेत है। राज्य में कार्रवाई कर रहे सुरक्षा बलों से भी कुछ मायलों में ज्यादाती हुई है। इस संबंध में दोषी लोगों को दंडित किये जाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की गई है। लोगों की शिकायतों को दूर करने और राजनीतिक प्रक्रिया को पुनः बहाल करने के प्रथम कदम के रूप में राज्य स्तर पर एक बहुदलीय सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है, ताकि वह परिषद् प्रशासन और लोगों के बीच सेतु का कार्य कर सके। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर समितियां बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। अक्टूबर, 1992 में एक संसदीय शिष्टमंडल ने घाटी का दौरा किया। राज्य में लोक-तांत्रिक प्रक्रिया की बहाली की दिशा में वातावरण तैयार करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया है।

पंजाब में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद राज्य के लोगों के जीवन में भारी सुधार हुआ है। अलगाववादी और विघटनकारी ताकतों के खिलाफ स्पष्ट संदेश देने के लिए इन बहादुर लोगों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। राज्य में लगभग 13 वर्ष के अन्तराल के बाद नगर पालिका के चुनाव हुए हैं और लगभग 9 वर्ष के अन्तराल के बाद पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हुए

हैं। इन चुनावों से नई उमंग और उत्साह पैदा हुआ है। राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास पर नए सिरे से बल दिया जा रहा है। सरकार पंजाब में सभी अनसुलझे मसलों का उचित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने और राज्य सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ किए जा रहे उपायों के लिए उसे सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की गति में, विशेष रूप से रेल, सड़क और दूर संचार में तेजी लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकारों और पूर्वोत्तर परिषद ने कृषि, वागवानी और मत्स्य पालन आदि के विकास के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। केन्द्र सरकार एक कृषि विश्वविद्यालय और एक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कर रही है। विकास के इन सभी कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी पर बल दिया जा रहा है। नागालैण्ड और मेघालय में हाल ही में चुनाव सम्पन्न हुए हैं।

पिछले वर्ष एक अप्रैल को शुरू हुई आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 1991-92 की कीमतों पर कुल निवेश 7 लाख 98 हजार करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इस निवेश में से सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 4 लाख 34 हजार एक सौ करोड़ रुपए होगा। हमारी आर्थिक नीति में हुए परिवर्तनों के अनुसार अब हम निर्देशात्मक योजना को और बढ़ रहे हैं।

वर्ष 1992-93 में आर्थिक स्थायित्व के कार्यक्रम और संरचनात्मक सुधारों की प्रक्रिया और अधिक मजबूत हुई है। वर्ष 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत थी और वर्ष 1992-93 में यह दर लगभग 4 प्रतिशत होने की आशा है। पिछले वर्ष के गति-रोधों, औद्योगिक क्षेत्र की अपेक्षाकृत धीमी गति और वित्तीय क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह वृद्धि दर अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

वर्ष 1992-93 में औद्योगिक उत्पादन में अप्रैल से अक्टूबर, 1992 तक की अवधि में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग एक प्रतिशत की कमी आई थी। इसी प्रकार अप्रैल-दिसम्बर 1992 की अवधि में निर्यातों में डालर के रूप में लगभग 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में 3.7 प्रतिशत की कमी आई थी। ऋणों की अदायगी के सम्बन्ध में रूस के साथ हाल ही में हुए करार से रूस में परम्परागत बाजारों को किए जाने वाले हमारे निर्यातों को फिर से प्रारम्भ करने में मदद मिलेगी। हमारे पास 5 बिलियन अमरीकी डालर की पर्याप्त विदेशी मुद्रा रिजर्व है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करके सरकार के एक प्रमुख उद्देश्य को पूरा कर लिया गया है, क्योंकि मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो अगस्त, 1991 में 16.7 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जनवरी, 1993 के अन्तिम सप्ताह में घट कर 7 प्रतिशत रह गई है।

हाल ही में विदेशी मुद्रा संबंधी नियन्त्रणों को उदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। नई आर्थिक नीति से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की हमारी कार्यविधि भी काफी उदार हो सकी है। अगस्त 1991 से जनवरी 1993 के अंत तक अनुमोदित कुल इक्विटी निवेश 2.3 बिलियन अमरीकी डालर से भी अधिक हो गया है, जो लगभग 35 हजार करोड़ रुपए के मूल्य की परियोजनाओं के लिए पर्याप्त होगा। लगभग 25 करोड़ डालर की विदेशी इक्विटी राशि वाले कई ऐसे अन्य प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं, जिससे 7,500 करोड़ रुपए के कुल मूल्य की परियोजनायें शुरू की जा सकती हैं। इनमें से अधिकांश निवेश प्राथमिकता के क्षेत्रों में है, जैसे : ऊर्जा के क्षेत्र में 24 प्रतिशत, पेट्रोलियम में 26 प्रतिशत, रसायन में लगभग 8 प्रतिशत, खाद्य संसाधन उद्योग में लगभग 12 प्रतिशत और विद्युत उद्योग में 8 प्रतिशत। शेष 22 प्रतिशत परिवहन, टेक्सटाइल, दूर चार और औद्योगिक मशीनरी के लिए

है। गैर प्राथमिकता वाली उपभोक्ता मद 4 प्रतिशत से कुछ कम है।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन करके उसे प्रभावी बनाया गया है, जिससे औद्योगिक कामगारों को पुनर्गठन की प्रक्रिया से नुकसान न पहुंचे। नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन का नवीकरण किया जाना इसका पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष, कार्यशील पूंजी, पुनःप्रशिक्षण एवं पुनर्वास उपायों तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीमों के लिए धन मुहैया करायेगा। यह स्कीम बहुत तेजी से प्रगति कर रही है और अब तक लगभग 22,000 कामगारों को इससे लाभ प्राप्त हुआ है।

सरकार ने सुधार प्रक्रिया से संबंधित सामान्य मुद्दों पर तथा क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट मामलों पर श्रमिक प्रतिनिधियों से परामर्श किया है। श्रम राज्य मंत्रियों की बैठक और भारतीय श्रम सम्मेलन में हमारे औद्योगिक संबंध विषयक विधियों को नवीकृत करने के मामले की जांच की गई है। सरकार इन परिवर्तनों को उच्च प्राथमिकता देती है क्योंकि यह आशा की जाती है कि इनसे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी, मजदूरों की आय अधिक होगी और औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण होंगे।

हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि यह बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर जुटाने और देश में चारों ओर औद्योगिक गतिविधियों को फैलाने में सक्षम है। वर्ष 1992-93 में लघु क्षेत्र में 129 लाख व्यक्तियों के रोजगार में होने और कुल उत्पादन एक लाख 66 हजार 4 सौ करोड़ रुपए का होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 4 प्रतिशत की वृद्धि दर की दर्शाता है। औद्योगिक क्षेत्र में काम की धीमी गति को देखते हुए इसे सराहनीय कहा जा सकता है। पूरे उद्योग क्षेत्र में नवीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग क्षेत्र के निष्पादन में वर्ष 1993-94

के दौरान महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। लघु युनिटों की बकार्या राशि का अन्य उद्योगों द्वारा तुरन्त भुगतान कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। अब माल प्राप्त करने या सेवायें प्रदान किए जाने के तीस दिन के भीतर भुगतान कर देना अपेक्षित होता है।

आज पूरे विश्व में यह बात स्वीकार की जा रही है कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक शक्ति उसके उत्पादन की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और कीमत के आधार पर अन्तरराष्ट्रीय बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पर निर्भर होगी। अतः हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम अगले कुछ वर्षों में डालर के रूप में 15-20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सतत निर्यात वृद्धि दर प्राप्त कर लें। सरकारी नीति का मूल आधार सभी सम्भव तरीकों से निर्यात को बढ़ावा देना और उसकी वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सभी बाधाओं या अवरोधों को दूर करना होगा।

कृषि भारतीय अर्थ-व्यवस्था और उसके जन-जीवन का मुख्य आधार है। चूंकि कृषि अभी भी पूर्णतः वर्षा पर ही निर्भर है, इसलिए वर्ष 1991-92 में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 90 लाख मीटरीक टन घट गया, जबकि उस वर्ष 16 करोड़ 70 लाख मीटरीक टन उत्पादन होने का अनुमान था। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उपभोक्ता कीमतों पर दबाव पड़ा है। लेकिन सीमित मात्रा में गेहूँ का आयात करने का निर्णय समय पर ले लिए जाने से उसकी कीमत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मई और दिसम्बर 1992 के बीच कीमतों में वृद्धि 3.6 प्रतिशत तक सीमित रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि चालू वर्ष में बिहार के भागों और कुछ अन्य राज्यों के भागों के सिवाय अच्छा मानसून रहा है। इस वर्ष कुल खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 10 करोड़ मीटरीक टन होने का अनुमान है,

जबकि पिछले वर्ष 9.142 करोड़ मीटरीक टन था। खरीफ के चावल की अधि-प्राप्ति संतोषजनक है और अब तक 90 लाख मीटरीक टन से अधिक की अधि-प्राप्ति की जा चुकी है। रबी की फसल अच्छी होने की संभावना है तथा एसी आशा है कि यह लगभग 7 करोड़ 60 लाख से 7 करोड़ 70 लाख मीटरीक टन तक होगी। खरीफ के तिलहन का उत्पादन लगभग 16 लाख मीटरीक टन तक हो गया है। अक्टूबर 1992 को समाप्त होने वाले चीनी-वर्ष में हमारा चीनी का उत्पादन 133 लाख मीटरीक टन था, जिसके फलस्वरूप भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया। इन सब बातों का कीमतों एवं उपलब्धता पर सराहनीय प्रभाव पड़ा है। कृषि क्षेत्र में देश की उपलब्धियां हमारे कृषकों के कटोर परिश्रम एवं उद्यम का स्पष्ट प्रमाण है।

हमारी कृषि योजनाओं का लक्ष्य केवल आत्मनिर्भर होना नहीं है। हमारी दृष्टि में यह एक ऐसा क्षेत्र है, जो कि अत्यधिक सम्भावना वाला है और किसानों तथा ग्रामीण मजदूरों को अधिक आय देने में सक्षम है। इस क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अगस्त 1992 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रु० प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया था और अप्रैल 1993 से प्रारंभ होने वाले बाजार-मीसम के लिए गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 55 रुपए क्विंटल बढ़ा दिया गया है। गेहूँ के लिए प्रति क्विंटल 25 रुपए का बोनस देने का भी निर्णय लिया गया है। गन्ने का न्यूनतम परिनिर्णय मूल्य चीनी वर्ष 1991-92 के लिए 3 रु० प्रति क्विंटल बढ़ा कर 26 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया था। चीनी-वर्ष 1992-93 में इसे और अधिक बढ़ा कर 31 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है। फोस्फेटिक तथा पोटेसिक उर्वरकों पर से कन्ट्रोल हटा लिए जाने के परिणामतः निःसंदेह थोड़े ही समय में उनकी कीमत बढ़ गई हैं। इस वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने एक बार की सहायता के रूप में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को 340 करोड़ रुपए दिए हैं। यूरिया की कीमत 10 प्रतिशत घट गई। सरकार ने छोटे एवं सीमित

किसानों के लिए कृषि के बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए 500 करोड़ रुपए को एक मुश्त सहायता देने की घोषणा की है। इन उपायों और आगामी वर्ष में शुष्क खेती पर अधिक ध्यान दिए जाने के कारण किसानों के हितों की काफी रक्षा होगी।

समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। सरकार ने इस योजना के तहत निर्धारित जनजातीय, सूखा पीड़ित, रेगिस्तानी एवं निर्दुष्ट पहाड़ी क्षेत्रों के 1700 ब्लॉकों में प्रति वर्ष वितरण के लिए 20 लाख मीट्रीक टन अतिरिक्त खाद्यान्न अलग से रखने का निश्चय किया है। जब से नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई है, तब से इन ब्लॉकों में 10,121 नई उचित दर दुकानें खोली गई हैं और 26 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं।

चालू वर्ष के दौरान जिला स्तर पर उपभोक्ता समाधान एजेंसियों के गठन से संबंधित कार्य आगे बढ़ाया गया और मेघालय राज्य के सिवाय समूचे देश में जिला फोरम बनाए गए हैं। इस समय देश भर में 447 जिला फोरम कार्य कर रहे हैं।

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आठवीं योजना में ग्रामीण बुनियादी आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों के साथ जवाहर रोजगार योजना को और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को एकीकृत करने पर अत्यधिक बल दिया गया है, जिससे ऐसी स्थायी और उत्पादक आर्थिक परिसंपत्तियां सृजित की जा सकें, जिनसे और अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों। सातवीं योजना में आवंटित छः हजार एक सौ उन्नासी करोड़ रुपए और वास्तविक व्यय दस हजार नौ सौ छपन करोड़ रुपए की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए परिष्यय बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991, जिसे पिछले सत्र में संसद् के दोनो सदनों ने पारित कर दिया है, अधिनियमित किए जाने पर कार्यात्मक रूप में नियमित चुनावों को सुनिश्चित करके तथा शक्तियों एवं वित्तीय संसाधनों के पर्याप्त हस्तांतरण द्वारा पंचायती राज संस्थानों को प्रभावी रूप में सुदृढ़ करेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था ग्रामों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की गई है। जिन सीटों के लिए सीधे ही चुनाव कराए जायेंगे, उनमें से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए नियत की गई हैं। इस कानून में अध्यक्ष के पद के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। यदि राज्य विधान मंडल चाहे तो पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं।

नगर पालिका शासन को सुदृढ़ बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि नगर पालिकायें स्थानीय सरकार की प्रभावी इकाई के रूप में कार्य करें, संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक, 1991 पारित किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, जैसा कि पंचायत के मामले में पहले किया गया था।

वर्ष 1992-93 के दौरान सरकार ने रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है। इन कार्यक्रमों में 2000 ई० तक एड्स नियंत्रण, कुष्ठ रोग के उन्मूलन, जनजाति क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण और पिछड़े क्षेत्रों में तपेदिक के उपचार के लिए अल्पकालिक केमो-चिकित्सा भी शामिल है। मौतियाबिंद के कारण होने वाले अंधेपन के उपचार के लिए सात

राज्यों में गहन कार्यक्रम चलाये जाने का प्रस्ताव है।

1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर, जो 1971—81 के दशक में 2.22 प्रतिशत तक पहुँच गई थी, घटकर 2.14 प्रतिशत रह गई है। सन 1990 में प्रति एक हजार की जनसंख्या पर जन्म-दर 30.2 थी, जो 1991 में घटकर 29.3 रह गई है, किन्तु 1.95 प्रतिशत की वर्तमान मूल वृद्धि दर अभी भी बहुत अधिक है। अतः जनसंख्या के स्थिरीकरण को सर्वाधिक राष्ट्रीय प्राथमिकता दी जाएगी।

अगले पांच वर्षों में चार लाख सफाई कर्मचारियों की मक्ति और उनके पुनर्वास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया गया है। सफाई कर्मचारियों के लिए एक सांविधिक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जा रहा है, जो इस कार्यक्रम का प्रभारी होगा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 125 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह निगम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लाभ के लिए आय उत्पन्न करने वाली स्कीमों के लिए धन प्राप्त में निरंतर सहायता करता रहेगा। अब तक निगम ने 277.63 करोड़ रुपए मूल्य की 312 स्कीमों मंजूर की हैं, जिसमें से अब तक 54.05 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं। यह निगम रोजगार और स्व-रोजगार हेतु कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए 48 जिलों में आवासीय विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

डा० वाबा साहेब अम्बेडकर के शताब्दी समारोह वर्ष में उनकी स्मृति को श्रद्धा-जाति के रूप में डा० अम्बेडकर राष्ट्रीय

पुरस्कार, डा० अम्बेडकर राष्ट्रीय पुस्तकालय, विश्वविद्यालयों में डा० अम्बेडकर पीठों और डा० अम्बेडकर विदेश शिक्षा वृत्ति जैसी स्कीमों का प्रबन्ध करने के लिए डा० अम्बेडकर फाउण्डेशन की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने डा० अम्बेडकर की सम्पूर्ण कृतियों और उनके भाषणों के अनुवाद और प्रकाशन का कार्य भी आरम्भ कर दिया है। डा० अम्बेडकर पर एक पूरी फीचर फिल्म का भी निर्माण किया जाएगा।

राष्ट्रीय पिछड़ी जाति वित्त और विकास निगम, जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 200 करोड़ रुपए है, वित्त का एक अतिरिक्त जरिया होगा और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों में तकनीकी और उद्यम कौशलों को बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगा।

संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 पारित कर दिया है, जिसमें इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और इसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ दी गई हैं। आयोग के मुख्य कार्य होंगे—अल्पसंख्यकों की प्रगति और उनके विकास का मूल्यांकन करना, संवैधानिक सुरक्षा उपायों को मानीटर करना और उन पर सिफारिशें करना, विशिष्ट शिकायतों को देखना, अध्ययन और अनुसंधान करना, उपयुक्त उपायों का सुझाव देना और समय-समय पर सरकार को रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू करने के लिए सरकार ने कार्रवाई आरम्भ कर दी है। सरकार सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों और वर्गों को, सम्पन्न व्यक्तियों को अन्य पिछड़ी जातियों में से निकालने के लिए संबंधित सामाजिक-आर्थिक मानदंडों को लागू करते हुए आधार विनिर्दिष्ट करेगी। नागरिकों की अन्य पिछड़ी जातियों की सूचियों में शामिल करने के लिए किए गए अनुरोधों और विनिर्दिष्ट जातियों से अधिक अथवा कम जातियों को शामिल करने के संबंध में

की गई शिकायतों पर विचार करने, उनकी जांच करने और उन पर सिफारिश करने के लिए एक स्थाई निकाय गठित करने के लिए अध्यादेश जारी किया गया है। इस निकाय द्वारा दी गई सलाह समान्यतः सरकार के लिए बाध्यकारी होगी।

अनौपचारिक क्षेत्र में निर्धन महिलाओं की अल्पावधि और मध्यम अवधि के विकासात्मक ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार का प्रस्ताव गैर सरकारी संगठनों जैसी मध्यवर्ती एजेंसियों के माध्यम से एक राष्ट्रीय महिला कोष स्थापित करने का है। सामाजिक सुरक्षा नेट के रूप में किए जा रहे प्रयासों के एक भाग के रूप में इस कार्यक्रम के लिए निधि का आवंटन कर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा की गई है, और मई, 1992 में इस नीति में आवश्यक संशोधन किए गए। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वतोमुखी बनाना, सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त करना, शैक्षिक अवसरों की समान सुलभता, महिलाओं की शिक्षा और विकास, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, उच्च शिक्षा का एकीकरण, तकनीकी शिक्षा का आधुनिकीकरण और सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता, विषयवस्तु एवं प्रक्रिया में सुधार करना शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे विषय हैं, जो राष्ट्रीय प्रयत्नों में अपना प्राथमिक स्थान बनाए हुए हैं। प्रारंभिक शिक्षा में हमने अपना ध्यान केवल छात्रों का नाम दर्ज किए जाने से हटकर इस बात पर केंद्रित कर दिया है कि उनकी उपस्थिति बनी रहे और शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो। संशोधित नीति में यह सुनिश्चित करने का संकल्प किया गया है कि इस दशक में 14 वर्षों तक की आयु के सभी बच्चों को संतोषप्रद गुणवत्ता वाली निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध हो जाए। संपूर्ण साक्षरता अभियाननीति पर आधारित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को प्रशंसनीय परिणामों की उपलब्धि हुई है और वर्ष 1996-97 तक देश के 75 प्रतिशत जिलों को इस मिशन के अंतर्गत लाया जाएगा। आगामी वर्षों में शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में स्वस्थ प्रबंधन सिद्धांतों को

अनुप्राणित करने और शैक्षिक प्रबंधन को विकेंद्रित करने पर बल दिया जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्साहवर्धक प्रगति हुई है। मई 1992 में ए एस एल वी का सफल प्रक्षेपण स्वदेशी प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण विकास है। जुलाई, 1992 में किया गया इन्सेट-2 ए का प्रक्षेपण और उसका सफलतापूर्वक कार्य प्रारंभ कर देना परिष्कृत बहु-उद्देशीय उपग्रह बनाने की हमारी क्षमता का सूचक है। इस वर्ष जून में इन्सेट-2 बी और पी एस एल वी का प्रक्षेपण करने की योजना से हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। अंटार्कटिका में 11 वीं वैज्ञानिक खोज यात्रा पूरी कर लेना और 12 वें अभियान का आरंभ करना वर्ष 1992 में किए गए अन्य उल्लेखनीय निकाय कार्य हैं। कृषि और स्वास्थ्य से संबंधित प्रौद्योगिकी साधन का लाभ उठाने के संबंध में जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें जारी रखा जाएगा।

इस वर्ष परमाणु उर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है—3 सितम्बर, 1992 को 220 मेघावाट के काकरापारा एटोमिक पावर स्टेशन यूनिट-1 का चालू किया जाना तथा 24 नवम्बर 1992 को इसे ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाना।

हमारे सशस्त्र बल हमारी क्षेत्रीय स्थिति की सुरक्षा करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। जन-शक्ति योजना और प्रबंधन कार्य में सुधार और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के संबंध में किए गए निवेदनों के अब अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

सशस्त्र बलों ने इस वर्ष अनेक अवसरों पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और राहत और वचाव कार्य करने में सिविल प्राधिकारियों की सहायता की है। उन्होंने अपना कार्य प्रशंसनीय समर्पण की भावना से किया है।

रजा-उत्पादन के क्षेत्र में, विशेष रूप से अतिरिक्त पुर्जों के स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के संबंध में सुदृढ़ प्रयास किए गए हैं। परिवर्तित औद्योगिक नीतियों को ध्यान में रख कर ही रक्षा और सिविल क्षेत्र की उत्पादन यूनिटों के बीच के संबंधों की पारस्परिक सुदृढ़ता को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र बल के कर्मियों के कल्याण में वृद्धि करने के लिए सरकार बचनबद्ध है।

हमने अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फोरम दोनों में दृढ़तापूर्वक अनुसरण किया है। पड़ोसी देशों के साथ संबंध और सुदृढ़ करने पर बल दिया गया और इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इन देशों में जिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भारत का दौरा किया, उनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति, बंगलादेश की प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री और भूटान नरेश भी शामिल हैं। इन दौरों के परिणामस्वरूप इन देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। बंगलादेश की प्रधानमंत्री के दौर के समय बंगलादेश को तीन बीघा का गलियारा पट्टे पर सौंप देने की हमारी बचनबद्धता पूरी की गई थी। भूटान नरेश के आगमन के समय महत्वपूर्ण संकोष बहुउद्देशीय परियोजना के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य करने हेतु दोनों देशों के बीच एक सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर और पंजाब में लगातार आतंकवाद और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों में मदद दिए जाने के बावजूद हमने विभिन्न द्विपक्षीय समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष दो बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत की। दुर्भाग्यवश हमारे प्रयासों से इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। हम पाकिस्तान से अनुरोध करते हैं कि वह जानबूझकर कोई

विवाद खड़ा न करे और भड़काने वाली कार्यवाहियों से दूर रहे तथा हमारे साथ अपने सम्बन्धों का एकतरफा लाभ उठाने के लोभ से बचे। द्विपक्षीय बातचीत के अभाव में हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है।

पुराने मतभेदों को भुलाकर सरकार लगातार चीन के साथ एक अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध बनाने की नीति पर चल रही है। हम सीमा सम्बन्धी विवाद का एक निरास, उचित और दोनों पक्षों को स्वोकार्य हल निकालने का भी प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं में से एक यात्रा हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरामन की थी। इस वर्ष चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा पर आने की संभावना है। हमारे प्रधानमंत्री भी चीन की यात्रा पर आएंगे।

हम अमरीका के राष्ट्रपति श्री क्लिंटन तथा उनके प्रशासन के साथ मिलकर आपसी सहमति, विश्वास और साझा मूल्यों तथा समान हितों के आधारे पर दोनों देशों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के इच्छुक हैं। शीत युद्ध को समाप्ति के बाद बढ़ती हुई अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत-अमरीका संबंधों को मजबूत करने की दिशा में गति आई है, जिससे कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग के साथ-साथ राजनीतिक स्तर पर भी दोनों देशों के बीच समझबूझ की भावना बढ़ी है।

राष्ट्रपति येल्लसिन को यात्रा से द्विपक्षीय और अन्तरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचारों के विस्तृत आदान-प्रदान का मौका मिला है। कश्मीर के सम्बन्ध में हमने अपनी स्थिति स्पष्ट की। राष्ट्रपति येल्लसिन ने स्पष्ट रूप से भारत को अपने देश का पूरा समर्थन दिए जाने की बात कही है। इस यात्रा के दौरान ऋण की अदायगी के मुद्दे को सुलझाया गया तथा कई करारों पर हस्ताक्षर किए गए जिससे कि दोनों देशों के बीच भावी मित्रता और घनिष्ट सम्बन्धों की मजबूत नींव रखी जा सकी है।



पिछले महीनों में हमें पश्चिमी यूरोप के तीन महत्वपूर्ण शासनाध्यक्षों का अपनी भूमि पर स्वागत करने का अवसर मिला है। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री जॉन मेजर हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। उनकी यात्रा से भारत-ब्रिटेन मैत्री और सहयोग बढ़ा है तथा लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त पर कायम रहने की हमारी प्रतिबद्धता के प्रति ब्रिटेन की सहमति की फिर से पुष्टि हुई है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में पूरा सहयोग देने का वायदा किया है। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इससे भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और अधिक बढ़ावा मिला है। इस महीने के शुरू में हमने स्पेन के राष्ट्रपति श्री फिलिप गोंजालेज का स्वागत किया। हाल ही में जर्मनी के चांसलर हेल्मुट कोल अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए अवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्राप्त करने भारत की यात्रा पर आए। इन महत्वपूर्ण यात्राओं से इस बात का परिचय मिलता है कि देश के सामने उपस्थित विभिन्न समस्याओं को सुलझाने की हमारी क्षमता तथा हमारी लोकतांत्रिक एवं सर्वधर्म सम्मान की प्रणाली की मजबूती की सराहना विदेशों में हो रही है। इन यात्राओं से हमारी विदेश नीति और हमारे आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों को और अधिक समर्थन मिला है।

यह संयोग की बात है कि भारत और जापान के बीच राजनयिक सम्बन्धों को चालीसवीं वर्षगांठ पर वर्ष 1992 में प्रधान-मंत्री जापान की यात्रा पर गए और उन्होंने दोनों देशों के बीच शान्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। हमारी आर्थिक उदारकरण की नीति में जापान की दिलचस्पी बढ़ने का इस बात से पता चलता है कि भारत में जापान के प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि हुई है। हम सभी स्तरों पर जापान के साथ सम्बन्धों को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध हैं।

हमने मध्य एशिया के नव स्वतंत्र देशों के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया है, जिनके साथ हमारे वर्षों पुराने सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं। पिछले वर्ष उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपतियों की भारत यात्रा के बाद मध्य एशिया में भारत उच्चस्तरीय यात्राएं हुईं। कुछ दिन पहले ताजकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। इस यात्रा के दौरान रेत करारों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनके मध्य एशिया के सभी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को एक नया और दीर्घकालीन आयाम मिला है।

सामरिक महत्व के आणविक भंडारों में कमी लाने के लिए अमरीका और रूस के बीच हुई स्टार्ट-II संधि का हम स्वागत करते हैं तथा इसे सही दिशा में उठाया गया कदम मानते हैं। बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में सांयनिक अस्त्र समझौते का सफलतापूर्वक सम्पन्न होना एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें व्यापक विनाश के सभी प्रकार के हथियारों को समाप्त करने की व्यवस्था है। यह एक विश्वव्यापी और भेदभाव रहित संधि है, जिस भविष्य में होने वाली वार्ताओं के लिए एक आदर्श के रूप में देखा जाना चाहिए। यह व्यापक निरस्त्रीकरण के लिए भारत की काय योजना को एक दृढ़ आधार प्रदान करती है, जिसे 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किया था। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणामों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय अथवा उप-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की नहीं अपितु एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

समय की आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पुनः शक्तिशाली हो और इसकी कार्यसूची अधिक सुस्पष्ट हो। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी संरचना को प्रजातांत्रिक बनाये और व्यवस्थित करने में कितना सक्षम है कि

यह अपने सदस्यों की चिन्ताओं का समायोजन और प्रतिबिम्बन कर सके।

संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष आन्दोलन, राष्ट्रमंडल और ग्रुप-15 में बहुपक्षीय स्तर पर हमारी सहभागिता अपनी प्राथमिकताओं और चिन्ताओं के सामान्य ढांचे के अंतर्गत ही रही है। पिछले सितम्बर में जकार्ता में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण से विचार-विमर्श का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसमें गुट निरपेक्ष आन्दोलन की सतत सार्थकता पर पुनः बल दिया गया और भावी कार्यसूची की प्राथमिकता दी गई ताकि इसकी विशिष्ट चिन्ताओं के मामलों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।

रियो डी जेनेरियो में जून, 1992 में हुए पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू एन सी ई डी) के दौरान प्रधानमंत्री के भाषण में पर्यावरण और विकास के बीच अभिन्न संबंध बनाए रखने पर जोर दिया गया, जो पर्यावरण तथा विकास संबंधी सभी मसलों को हल करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। विकासशील देश पर्यावरण की सुरक्षित रखने के व्यापक प्रयास में विकसित देशों के साथ शामिल हो सकें, इसके लिए उनको प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने तथा अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के भारत के प्रस्ताव का सम्मेलन में व्यापक स्वागत तथा समर्थन किया गया।

माननीय सदस्यगण, देश आज जिस संकट के दौर से गुजर रहा है, उसमें आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी आ पड़ी है। पिछले वर्ष जहां आपने उल्लेखनीय स्तर पर

सहयोग देखा, वहीं असहमति के प्रबल पक्ष भी देखे। ये सब एक जीवन्त लोकतन्त्र को प्रदर्शित करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष समस्याओं से निपटने के लिए आप पूरे देश के समक्ष अपने उल्लेख्य आचरण और नेतृत्व का परिचय देंगे। राष्ट्र इस महान संस्था के प्रतिनिधियों से इससे कुछ भी कम की आकांक्षा नहीं रखता। आपको साहस, बुद्धिमता और अनुशासन के साथ राष्ट्र का मार्गदर्शन करना है।

मैं आपका आभूत कर्ता हूँ कि इस अधिवेशन में आप अपने कार्य में जुट जाएं और इसके लिए आपकी सकलता की कामना करता हूँ।

जय हिन्द

[Text of the President's Address in English.]

Hon'ble Members,

I welcome you to this session of Parliament.

The most important task before us today is to restore confidence and communal amity which have been shaken by the tragic events of the 6th of December last year and what followed thereafter. The basic premise of secularism and the rule of law has been threatened. Political parties, intellectuals-opinion leaders and others must all strive to counter the communal propaganda that has been let loose so that the country can proceed with the task of building the nation and reasserting our fundamental values. We have to further strengthen the harmony that has allways characterised our society.

The Central issue of the Ram Janmabhoomi-Babri Masjid dispute has been referred to the Supreme Court under article 143 of the Constitution. Government has also acquired about 68 acres of land in the complex, and is in the process of setting up two

separate Trusts for managing the construction of Ram temple and Mosque. Government's endeavour will be to ensure that the construction is taken up in consultation and cooperation with the two communities concerned and with the active participation of eminent and responsible leaders of the two communities. Government seeks the support and cooperation of all sections of the people in this important endeavour.

In Jammu and Kashmir there has been no let-up in the involvement of forces from across the border in training, arming and providing logistic support to the terrorists. Our security forces—despite having to work under extremely difficult conditions, have been trying to meet this challenge. Government is acutely conscious of the hardships and privations of the people of Jammu & Kashmir arising from the inli-midatory acts of terrorists, frequent calls for bandhs and disruption of economic and commercial activity in the State—There have also been some cases of excesses by security forces operating in the State. Prompt action has been taken in such cases to punish those found guilty. As a first step to redress the grievances of the people and reactivate the political process, a State level multi-party advisory council has been set up to act as a bridge between the administration and the people. Efforts are also being made to set up district level committees to carry the process forward. A Parliamentary delegation visited the valley in October 1992. Discussions have been held by the Union Home Minister with leaders of political parties to create conditions which would enable democratic processes to be restored.

After the democratically elected government assumed office in Punjab, there has been a dramatic improvement in the life of the

people of the State. These brave people deserve all credit for sending a clear message against the forces of separatism and disruption. Elections to municipalities were held after a gap of about 13 years and to panchayats, after a gap of about 9 years. These have evoked massive and enthusiastic response. A renewed thrust as is being given to the socioeconomic development of the State. The Centre remains committed to finding a just and amicable solution to all the outstanding issues in Punjab and will provide all assistance to the State Government in its pursuit of anti-terrorist measures.

The overall situation in the North-Eastern region has been under control. Steps have been taken to accelerate the pace of infrastructure development in the region, particularly in respect of rail, road and telecommunications. State Governments and the North-Eastern Council have initiated new programmes for development of agriculture, horticulture and fisheries. The Central Government is setting up an agricultural university and an institute of technology. In all these programmes of development, people's participation is being emphasised. Elections have been held recently in Nagaland and Meghalaya.

The implementation of the Eighth Plan—launched on April 1 last year, is well under way. The total investment has been substantially stepped up to Rs. 7,98,000 crores at 1991-92 prices. Out of this the public sector outlay will be Rs. 4,34,100 crores. We are moving towards indicative planning which is in tune with the changes that have been initiated in our economic policy.

The year 1992-93 witnessed a further consolidation of the economic stabilisation programme and the

Process of structural reforms. The growth in GDP which was 1-2% in 1991-92 is expected to be around 4% in 1992-93. This growth is significant when viewed against the setbacks of the past year, the comparative slow-down in the industry Sector and problems in the financial sector.

During 1992-93 industrial production recorded an increase of 3.8% for the period April to October 1992 as compared to a decline of about 1.0% during the same period in the 1.0% during 1991-92. Similarly exports recorded a growth of around 3.4% in dollar terms during April-December 1992 compared to a decline of 3.7% in the corresponding period of the previous year. The recent agreement with Russia on the repayment of debt will help to revive our exports to traditional markets in

Russia. We have comfortable foreign exchange reserves of US \$ 5 billion. One of the prime objectives of Government, namely control of inflation has been achieved, as the annual rate of inflation which peaked at 16.7% in August 1991 was brought down to 7.0% in the last week of January 1993.

Major changes have been made recently to liberalise foreign exchange controls. The new economic policy has also led to major liberalisation in our procedures for foreign direct investment. The total equity investment approved from August 1991 to the end of January 1993 is over \$ 2.3 billion which will account for projects of a value of about Rs. 35,000 crores. A number of other proposals are also in the pipeline- with a foreign equity component of about \$ 250 million, generating projects with a total value of Rs. 7,500 crores. Most of these investments are in priority sectors: 24% in energy, 26% in petroleum- about 8% in chemicals- about 12% in food processing industry and 8% in electrical industry. The remaining 22%

includes transportation, textiles, tele communications and industrial machinery. Non-priority consumer items account for a little less than 4%.

The National Renewal Fund was set up and operationalised so that the industrial workers are not hurt in the process of restructuring. The first major programme being taken up is the turnaround of the National Textile Corporation in which the National Renewal Fund will provide funds for working capital, retraining and rehabilitation measures and voluntary, retirement schemes. The scheme has been making steady progress so far and about 22,000 workers have been covered.

Government has held consultation with labour representatives on general issues concerning the reform process as well as sector-specific matters. A meeting of the State Labour Ministers and the Indian Labour Conference has also gone into the manner of revamping our industrial relations laws. Government attaches high priority to these changes as they are expected to lead to increased production and productivity- high wage earnings and harmonious industrial relations.

The small scale sector is of very great importance in our industrial economy because of its potential for high levels of employment generation and the dispersal of industrial activity across the country. In 1992-93, the employment in the sector was estimated at 129 lakh persons and total production was expected to be at Rs. 1,66,400 crores- representing a rate of growth of 4% over the previous year. In view of the slow-down in the industrial sector this was creditable. With revival in industry as a whole, the performance of the small scale sector is expected to improve very significantly in 1993-94. An important initiative to ensure prompt payment by other industries of the dues of the small scale units has been taken. Payments are now required to be made

within thirty days of acceptance of goods or rendering of service.

In the world that is emerging, the economic strength of a nation will depend on its ability to compete in international market place, on the basis of quality, reliability and price. It should be our endeavour to achieve a sustained growth rate of exports of 15—20% per annum in dollar terms within the next few years. It would be a basic plank of Government policy to encourage exports in every possible way and to remove all impediments or constraints that affect their growth.

Agriculture is the mainstay of the Indian economy and its people- As it is still essentially dependent upon rainfall, there was a drop in foodgrains production in 1991-92 by about 9 million tonnes and was estimated at 167 million, tonnes. This brought the Public Distribution System and consumer prices under pressure. However, the timely decision to import a limited quantity of wheat has had a positive impact on its price behaviour. The increase in prices between May and December 1992 was restricted to 3.6% compared to a rise of 35% during the corresponding period in the previous year. I am happy to say that in the current year, the monsoon has been good excepting in parts of Bihar and in parts of a few other States. The total Kharif foodgrains production is estimated at 100 million tonnes against last year's 91.42 million tonnes. Procurement of Kharif rice has been proceeding satisfactorily and has already crossed 9 million tonnes. The prospect of Rabi food production, good and it is expected to be around 76 to 77 million tonnes. Kharif oilseeds production has been higher by about 16 lakh tonnes. Our sugar production was 133 lakh tonnes in the sugar year ending October, 1992, thus making India the world's largest sugar producer. All this has had a salutary effect on prices as well as availability. The country's achievements in the agricultural sector

bear eloquent testimony to the hard work and enterprise of our farmers.

Our plans for agriculture go beyond mere self-sufficiency. We see it as an area with great potential, capable of yielding much higher incomes to farmers and rural labour. To stimulate growth in this sector the minimum support prices for paddy were increased by Rs. 40 per quintal in August, 1992 and for wheat for the marketing season starting 1 April 1993, by Rs. 55. It has also been decided to pay a bonus of Rs. 25 per quintal for wheat. The statutory minimum price of sugar-cane was raised by Rs. 3 per quintal to Rs. 26 for the sugar year 1991-92. This has been further raised to Rs. 31 per quintal for the sugar year 1992-93. The decontrol of phosphatic and potassic fertilizers has no doubt led to increase in their prices in the short-term. To cushion the impact of this increase, Government provided Rs. 340 crores to the State Governments and Union Territories as a one-time support. The price of urea was decreased by 10 Government has also announced a Rs. 500 crore package to develop agricultural infrastructure meant for the small and marginal farmers. These measures and the increased attention that dry farming would get in the coming year will serve the interests of the farmers in a big way.

One of the important programmes being implemented by the Government to protect the interests of the vulnerable sections of the society is the Revamped Public Distribution System. Government has decided to set apart and distribute an additional 20 lakh tonnes of foodgrains every year in the 1,700 blocks in the tribal, drought-prone, desert and designated hill areas of the country, identified under the scheme. Since the inception of the Revamped Public Distribution Scheme 10,121 new fair price shops have been opened in these blocks and 26 lakh additional ration cards have been issued.

During the current year, work relating to the setting up of district level consumer redressal agencies was carried forward and the entire country was covered by District Forums except the State of Meghalaya. 447 District Forums are presently functioning in the country.

The thrust of the Eighth Plan in the field of rural development is to integrate the Jawahar Rozgar Yojana and the Integrated Rural Development Programme with other on-going programmes for strengthening rural economic infrastructure so as to create durable and productive economic assets which in turn generate further employment. The outlay for rural development for the 8th Five Year Plan has been increased to Rs. 30,000 Crores as compared to an allocation of Rs. 6,179 crores and an actual expenditure of Rs. 10,956 crores in the 7th Plan.

The Constitution (72nd Amendment) Bill, 1991, which has been passed by both the Houses of Parliament in the last session, when enacted, will effectively strengthen Panchayati Raj institutions by ensuring regular elections and sufficient devolution of powers and financial resources. Provision for reservation of seats in the Panchayats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been made in proportion to their population in the village. Out of the seats for which direct election will be held, one third are reserved for women. Furthermore out of the seats, reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, one third will be earmarked for Scheduled Caste and Scheduled Tribe women. The law has provision for enabling reservations to be made for the office of Chairperson also. The State legislatures, if they so desire, can make reservations in favour of backward classes.

To strengthen municipal government and to ensure that municipa-

lities perform as effective units of local self-government, Parliament has passed the Constitution (73rd Amendment) Bill, 1991. Provision for reservation for members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribe women and Backward Classes have been made as in the case of Panchayats.

During the year 1992-93, Government gave priority to disease control programmes. These include control of AIDS, eradication of leprosy by the year 2000 AD, malaria control in tribal areas and short-term chemotherapy for tuberculosis in backward areas. An intensive programme is proposed to be taken up in seven States for dealing with cataract-induced blindness.

According to the 1991 Census, the average annual exponential growth rate of population which had reached a level of 2.22% in the 1971-81 decade has come down to 2.14%. The birth rate has come down to 29.3 per 1,000 population in 1991 from a level of 30.2 in 1990. However, the present natural growth rate of 1.95% is still very high and stabilisation of population will, therefore, be an overriding national priority.

A massive programme has been launched for the liberation and rehabilitation of 4 lakh safai karmacharis during the next five years. A Statutory National Commission for Safai Karmacharis is being constituted to be in charge of this programme.

The authorised share capital of the National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance & Development Corporation has been raised from Rs. 75 crores to Rs. 125 crores. The Corporation will continue to assist in the flow of funds for income generating schemes for the benefit of Scheduled Caste and Scheduled Tribe entrepreneurs. So far, the Corporation has sanctioned 312 schemes of a value of Rs. 277.63

crores towards which it has disbursed Rs. 54.05 crores. The Corporation is also organising training programmes in skill upgradation for employment and self-employment. To raise the levels of literacy and education amongst the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it is proposed to start residential schools in 48 districts.

As a tribute to the memory of Dr. B. R. Ambedkar during his Centenary Celebration Year, the Dr. Ambedkar Foundation was set up to administer schemes like the Dr. Ambedkar National Award, Dr. Ambedkar National Library, Dr. Ambedkar Chairs in Universities and Dr. Ambedkar Overseas Fellowships. In addition, the Government has also taken up the translation and publication of the complete works and speeches of Dr. Ambedkar. A full-length feature film on Dr. Ambedkar will also be produced.

The National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC), with an authorised share capital of Rs. 200 crores, will provide an additional channel of finance and assist in upgrading the technical and entrepreneurial skills of the socially and educationally backward classes.

The National Commission for Minorities Act, 1992 has been passed by Parliament providing statutory status to the Commission clothing it with the powers of a Civil Court. The main functions of the Commission would be to evaluate the progress of development of the minorities, monitor and make recommendations on the working of Constitutional safeguards, look into specific complaints, undertake studies and research, suggest appropriate measures and make periodical reports to Government-

Government has initiated action to implement the judgement of the

Supreme Court on issues relating to the reservation of jobs in Government for Backward Classes. Government will specify; the basis, applying the relevant and requisite socio-economic criteria, to exclude socially advanced persons and sections the creamy layer, from other backward classes- An ordinance has been promulgated to constitute a permanent body for entertaining, examining and recommending upon requests for inclusion and complaints of over inclusion and under inclusion in the lists of other backward classes of citizens. The advice tendered by such body shall ordinarily be binding upon the Government.

Government proposes to set up the Rshtriya Mahila Kosh to meet the short-term and medium term developmental credit needs of poor women in the informal sector through intermediary agencies like non-Government organisations. Funds have been allocated to this programme as part of the Social Safety Net efforts.

A review of the 1986 National Policy on Education has been undertaken and necessary modifications in the Policy were effected in May 1992. Universalisation of elementary educational achievement of total literacy equal access to educational opportunities, women's education and development, vocationalisation of secondary education, consolidation of higher education, modernisation of technical education, and improvement of the quality, content and process of education at all levels continue to be the priority areas of national endeavour in the field of education. In elementary education, we have shifted the focus from mere enrolment to retention and achievement. The revised policy resolves to ensure that free and compulsory education of satisfactory quality is provided to all children upto 14 years of age within this decade. The National Literacy Mission based on the Total Literacy Campaign strategy has

achieved commendable results and 75 of the districts in the country will be covered under this Mission by 1996-97. The emphasis during the coming years will be on infusing sound management principles in the education system and on decentralising education management.

There has been encouraging progress in the sphere of science and technology. The successful launch of ASLV in May, 1992 is a significant development in indigenous launch technology. The launch of INSAT-2A in July, 1992 and its successful commissioning is an indication of our ability to build sophisticated multi-purpose satellites. The planned launches of INSAT-2B and the PSLV in June this year will provide a further fillip to our Space programme. Another noteworthy development of 1992 was the completion of the 11th Scientific Expedition to Antarctica and the launch of the 12th expedition. Ongoing efforts to harness the benefits of biotechnological tools with relevance to agriculture and health; would be sustained.

The highlight of this year's achievements in the field of Atomic Energy has been the 220 MW Kakrapar Atomic Power Station Unit-I achieving criticality on September 3, 1992 and its synchronisation to the grid on November 24, 1992.

Our Armed Forces remain prepared to safeguard our territorial integrity. Improvements in manpower planning and management practices and investments towards self-reliance in defence technologies are yielding results.

The Armed Forces assisted the civil authorities in maintaining law and order and organising relief and rescue measures on a number of occasions during the year, carrying out their *tasks* with commendable dedication.

In the field of defence production determined efforts have been made towards indigenisation and self reliance particularly in spare parts. In keeping with the changed industrial policies steps are being taken to foster mutually reinforcing linkages between production units in the defence and civil sectors.

Government remains committed to enhance the welfare of serving and retired Armed Forces personnel.

Our foreign policy objectives were pursued both bilaterally and in international forums. Emphasis was placed on building up relations with our neighbours. Important visitors from these countries included the President of Sri Lanka, the Prime Minister of Bangladesh, the Prime Minister of Nepal and the King of Bhutan. Our ties with these countries have been strengthened as a result of these visits. During the visit of the Bangladesh Prime Minister, our commitment to lease the Tin Bigha corridor to Bangladesh was fulfilled. A Memorandum of Understanding between the two countries on detailed investigations for the important Sankosh multipurpose project was signed during the visit of the King of Bhutan.

Despite Pakistan's continuing support for terrorism and subversion in Jammu & Kashmir and Punjab, efforts were made by us to resolve various bilateral issues. With this objective in mind, the Prime Minister had two meetings with the Prime Minister of Pakistan in the course of the last year. Our efforts have unfortunately not made much headway. We urge Pakistan to eschew its path of deliberate and provocative confrontation and its temptation to gain unilateral advantage in its relationship with us. There can be no alternative to the process of bilateral dialogue.

Government has been consistently pursuing a policy of achieving good neighbourly relations with China overcoming the difficulties of the past. We are also working for a fair



reasonable and mutually acceptable settlement of the boundary question. Among the several high-level visits exchanged between the two countries last year was that of our former President, Shri R. Venkataraman. The Chinese Foreign Minister is expected to visit India this year. The Prime Minister will also be visiting China.

We look forward to working together with President Clinton and his administration in the United States in building a strong relationship between our two countries based on mutual understanding, trust and shared values and interests. The changed international environment following the end of the Cold War has given an impetus to the strengthening of Indo-US ties- which now reflect a greater degree of understanding at the political level along with growing cooperation in various other areas.

The visit of President Yeltsin provided the opportunity for a detailed exchange of views on all bilateral and global issues of concern. Our stand on Kashmir was explained. President Yeltsin categorically affirmed his country's full support for India's position. During this visit the debt repayment issue was resolved and several other agreements were signed which have laid a durable foundation for future friendship and close interaction between the two countries.

We had the pleasure of welcoming in our midst three distinguished Heads of Government from Western Europe. The British Prime Minister Mr. John Major- was here as Chief Guest at our Republic Day celebrations. His visit underscored India-U.K. friendship and cooperation and reconfirmed British understanding of our actions to uphold democracy and secularism. He extended full cooperation in combating terrorism. A further significant outcome of the visit was the stimulus it gave to India-British eco-

nomie and commercial cooperation. Earlier this month, we welcomed the President of the Government of Spain, Mr. Felipe Gonzalez. Most recently- Dr. Helmut Kohl, Chancellor of Germany visited India to receive the Jawaharlal Nehru Award for International Understanding. These significant visits reflect appreciation overseas of our resilience in addressing the various issues that face the country as well as the strength of our democratic and secular system. They have also resulted in greater appreciation of our foreign policy as well as in support for our economic reforms programme.

The Prime Minister's visit to Japan in 1992 coincided with the 40th anniversary of the establishment of diplomatic relations between India and Japan and the signing of a peace treaty between the two countries. Japanese interest in our economic liberalisation is underscored by the increase in direct Japanese investment in India. We are committed to strengthening our ties with Japan at all levels.

The strengthening of our relations with the newly independent countries of Central Asia with whom we have had age old cultural ties, is a major thrust of our policy. The visit to India last year of the President of Uzbekistan, Kazakhas-tan- Kyrgyzstan and Turkmenistan were followed up with high level visits from India to Central Asia. The Prime Minister of Tajikistan visited India a few days back. Agreements were signed during these visits which give our relations with the individual Central Asian State a new and long term perspective.

We welcome the TART-II Treaty between the United States and Russia for reduction in strategic nuclear arsenals as a step in the right direction. The unilateral disarmament agreement- a noteworthy event has been the successful

conclusion of the Chemical Weapons Convention, which eliminates an entire class of weapons of mass destruction. This is a universal and non-discriminatory treaty which should be regarded as a model for future multilateral disarmament negotiations. It provides a strong underpinning to the Indian Action Plan for Global Disarmament that Prime Minister Rajiv Gandhi had presented to the United Nations in 1988. A global- and not regional or sub-regional, approach is needed for worthwhile results in this area.

A reinvigorated United Nations with a more sharply focused agenda is the need of the hour. The effectiveness of the United Nations will depend on its ability to democratise and reorder its structures to accommodate and reflect the concerns of its members.

Our participation at the multilateral level in the U.N., NAM the Commonwealth and the G-15 has been within the overall framework of our priorities and concerns. The Prime Minister's address at the inaugural session of the Non-Aligned summit in Jakarta last September set the tone of its deliberations, reaffirming the continuing relevance of the Non-Aligned Movement and prioritising its future agenda so as to concentrate upon issues of specific concern to it.

At the UN Conference on Environment and Development (UN CED) in Rio de Janeiro in June, 1992, the Prime Ministers address emphasised the integral link between environment and development, thus marking a milestone in international cooperation in tackling environmental and development issues. India's proposal for transfer of technology to, and additional resources for, developing countries, to enable them to join their developed country partners in the global effort at preserving the environment,

was widely welcomed and endorsed by the Conference.

Honourable Members, the crisis the country is faced with today places a grave responsibility on your shoulders. You saw remarkable levels of cooperation as also strong areas of class last year. These are the essential manifestations of a living democracy. I am sure you will set the tone for the entire country to deal with its problems this year with exemplary conduct and leadership. The nation expects nothing less from its representatives here. You have to guide the nation with courage- wisdom and discipline.

I commend you to your tasks in this session and wish you all success.

J A I HIND

#### **OBITUARY REFERENCES**

MR. CHAIRMAN : Hon. Members- I refer with profound sorrow to the passing away of Shri Shraddha-kar Supakar, former Member of the Rajya Sabha, Shri Bindeshwari Dubey, a sitting Member of the House, Shri Biren Roy, Shri Mahitosh Purkayastha and Shri Baharul Islam, former Members of the Rajya Sabha,

Shri Shraddhakar Supakar was born in April- 1915 at Sambalpur and passed away on the 5th January, 1993 at the age of 78 years. He had his education at Cuttack and Patna. A lawyer by profession, Shri Supakar took keen interest in promotion of education and was closely associated with a number of educational institutions in various capacities.

Shri Supakar started his parliamentary career as a Member of the Orissa Legislative Assembly from 1949 to 1957 and served as Leader of the Opposition in the Assembly from 1952 to 1956. He was also the